द ब्रिक्स कनेक्ट

साभार : पायनियर
06 सितंबर, 2017

मनीष चंद
(संपादक, इंडिया एंड वर्ल्ड, मैगजीन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

डोकलाम पठार में व्याप्त गतिरोध की ध्वनि और रोष की गूंज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साफ तौर पर सुनाई देर रही है क्योंकि भारत और चीन ने ब्रिक्स के भवन को मजबूत करने के लिए अलग-अलग मतभेद स्थापित किए।

निश्चित तौर पर अब डोकलाम की समस्या समाप्त हो चुकी, अब बारी ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की है। यह सुन्दर तटीय शहर शियामेन (xiamen) में, अपने स्वादिष्ट नूडल्स, उद्यमशीलता ड्राइव और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, जहाँ अब इस सम्मेलन के बाद कई प्रश्नों का जन्म होने वाला है। हांलाकि, ब्रिक्स राष्ट्रों का उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र सिद्धांतों और बेबाक बयानबाजी के बजाय संक्रियाओं पर और आगे की ओर देखने से मालूम पड़ता है, क्योंकि चीन ने भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए ब्रिक्स संयुक्त घोषणा को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है।

आतंक कनेक्ट:

यह भारतीय कूटनीति की जीत थी, लेकिन यह आम खतरों से लड़ने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में ब्रिक्स की प्रमुख भूमिका का भी प्रतिबिंब था। 71-पैराग्राफ शियामेन घोषणा यदि आंशिक रूप से भी लागू की जाती है, तो भौगोलिक राजनीतिक संकट पर उभरती हुई शक्तियों के प्रति-बयान को मजबूत करने और विकासशील देशों की आकांक्षाओं को संभव बनाते हुए एक नई वैश्विक प्रशासन वास्तुकला को आकार दिया जा सकता है जो एक संभावित खेल-परिवर्तक साबित होगा।

भारत के दृष्टिकोण से प्रमुख दूरसंचार, आतंकवाद की दिक्कत पर एक मजबूत अभिसरण था जो पूरे क्षेत्र और विश्व में नए गरीबों में फैल रहा था। अतीत की झिझक को साफ करते हुए, ब्रिक्स देशों ने समस्त रूप से सीमा पार आतंकवाद के बारे में भारत की चिंताओं का समर्थन किया है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान के लश्कर-ए-तय्येबा (एलईटी), जैश ई-मोहम्मद (जेएएम) और हक्कानी नेटवर्क सहित भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए पहली बार एक ब्रिक्स संयुक्त घोषणा नाम शामिल है। शियामेन डिक्लेरेशन में कहा गया है कि, हम दुनिया भर में सभी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं, जिसमें ब्रिक्स देशों पर हुए हमले भी शामिल हैं और अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में जहां भी प्रतिबद्ध और आतंकवाद की निंदा करते हैं और जो भी और तनाव है कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

अफगानिस्तान में नाजुक और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति का हवाला देते हुए इस घोषणा में कहा गया है कि हम इस क्षेत्र इसके सहयोगी संगठनों जैसे तालिबान, इस्लामी राज्य, अलकायदा हुई हिंसा तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उज्बेकिस्तान के इस्लामिक आंदोलन, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और हिजबूत-तहरीर के द्वारा की जा रही हिंसा और सुरक्षा की स्थिति पर काफी चिंतित हैं।

शियामेन संयुक्त घोषणा में पाकिस्तान द्वारा समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों का स्पष्ट उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने पिछले साल गोवा में हुए इन आतंकवादी संगठनों को शामिल करने का विरोध किया था। हांलाकि, भारत द्वारा पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों को शामिल करना विश्लेषकों और ब्रिक्स पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि बीजिंग ने चेतावनी दी थी कि आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका 'शिखर सम्मेलन' के लिए एक उपयुक्त विषय नहीं है।

इन संगठनों से आतंकवादी होने के संबंध में भारत की चिंताओं का समर्थन करने के लिए चीन के कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन सूचित सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद के व्यापक विस्तार का एक हिस्सा था। एक संभावित स्पष्टीकरण भी आतंकवाद के बारे में बीजिंग की बढ़ती चिंताओं और इसके चरमपंथी ताकतों के प्रति संवेदनशीलता का कारण हो सकता है। गोवा में आखिरी शिखर सम्मेलन के विपरीत,

जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए उसे 'आतंकवाद की मातृभाषा' के रूप में पूरे विश्व को बताया था, इस बार अपने पूरे भाषण में पाकिस्तान या आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि, ब्रिक्स के नेताओं की प्रतिबंधित मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी ने तीव्रता से ब्रिक्स काउंटर-आतंक के सहयोग के लिए एक संयुक्त रणनीति की वकालत की है, जिसमें खुफिया शेयरिंग, डी-क्रांतिकारीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

अंत में, हालांकि, यह परिणाम मायने रखता है और इस प्रकार, ब्रिक्स रडार स्क्रीन पर एलईटी और जेएम के साथ आतंकवाद पर संयुक्त बयान, निश्चित रूप से भारत के लिए बेहद संतोषजनक होगा। यह संयुक्त वक्तव्य यह दर्शाता है कि निस्तब्ध कूटनीति अक्सर बयानबाजी वाले कूटनीति की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है।

दक्षिण-दक्षिण संबंध:

आतंकवाद के खिलाफ आगे बढ़ते हुए शियामेन शिखर उभरते हुए और विकासशील देशों के परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में ब्रिक्स सदस्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण जंक्शन का प्रतीक है। विश्व व्यवस्था के निरंतर पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि के खिलाफ, विकास सहयोग और भावी देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार के संबंधित क्षेत्रों में उन्नत साझेदारी एक और समरूप दुनिया बनाने में मदद करेगी। शी जिनपिंग के शहर में, जहां चीन के मुख्य नेता ने 32 साल पहले उप-महापौर के रूप में नवाचार और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित हुए एक परिवर्तनकारी कार्य किया था।

देखा जाये तो इस संबंध में, दोनों प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने एक ही स्वर में बात की है। प्रौद्योगिकी और नवाचार वैश्विक विकास और परिवर्तन की अगली पीढ़ी की नींव हैं। नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक मजबूत साझेदारी, विकास को बढ़ावा देने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सशक्त विकास लक्ष्यों को समर्थन देने में मदद कर सकता है। शी जिनपिंग ने बताया कि नवाचार से उत्पन्न आर्थिक सहयोग, ब्रिक्स तंत्र की नींव है।

वैश्वीकरण 2.0

शियामेन शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहल संरक्षणवाद और प्रतिगामी बयानबाजी की बढ़ती दीवारों के खिलाफ एक बांध के रूप में ब्रिक्स की भूमिका को एकजुट करना था, जिसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प शासन के उत्थान के बाद एक नया अनुभव और कुछ यूरोपीय देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय प्राप्त किया है। संयुक्त घोषणा वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार और एक खुले, समावेशी और संतुलित आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में ब्रिक्स समन्वय के महत्व को रेखांकित करता है।

इस संबंध में, ब्रिक्स संस्था-निर्माण और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शियामेन में 4 सितंबर को हस्ताक्षरित चार दस्तावेज, ब्रिक्स देशों के बीच विकास और आर्थिक सहयोग की वृद्धि को बढ़ाने का संकेत देते हैं। इनमें आर्थिक सहयोग पर ब्रिक्स एक्शन एजेंडा, नवाचार सहयोग (2017-2020) के लिए ब्रिक्स एक्शन प्लान, ब्रिक्स कस्टमस कॉरपोरेशन के स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और स्ट्रैटेजिक सहयोग पर नए विकास बैंक के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

एक और सुनहरा दशक

भविष्य की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ने 'एक और सुनहरे दशक' की बात कही है, लेकिन कथित सुनहरे दशक की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी डोकलाम जैसी संघर्षों से ब्रिक्स को बचाने में है, क्योंकि यह न सिर्फ ब्रिक्स को नुकसान पहुंचायेगा, बल्कि इस वजह से एशियाई शताब्दी के लिए किये गये बड़े-बड़े वादे कमजोर पड़ जायेंगे। डोकलाम संकट के संकल्प ने शियामेन में एक बेहद सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, लेकिन भारत और चीन को नई शुरुआत करने और मतभेदों पर ध्यान दिए बिना बड़े पैमाने पर सामंजस्यपूर्ण और भविष्य के रिश्ते के निर्माण के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करने की जरूरत है और वास्तव में यही समय उपयुक्त है, इसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए।

शी जिनपिंग ने कहा, ''राष्ट्रीय परिस्थितियों, इतिहास और संस्कृतियों में अंतर को देखते हुए, यह स्वाभाविक है कि हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने में कुछ अंतर हो सकता है।'' शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, हालांकि, सहयोग और मजबूत विश्वास के साथ, अन्य ब्रिक्स देश हमारे सहयोग में लगातार प्रगति हासिल कर सकते है। साथ ही इन्होने कहा कि ''मुझे भरोसा है कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को उसके समग्र रूप में देखेंगे और उसके लक्षणों के साथ ही साथ बुनियादी कारणों पर भी ध्यान देंगे तो आतंकियों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी।"

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि उभरते हुए विश्व के इस परिवर्तन को चलाने में ब्रिक्स नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। यदि हम ब्रिक्स के रूप में इन क्षेत्रों में अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, तो दुनिया हमारे सुनहरे भविष्य को देख सकेगी।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World

इससे संबंधित तथ्य

ब्रिक्स क्या है?

- ब्रिक्स उभरते हुए पाँच देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक संक्षिप्त शब्द है। पहले केवल चार ब्रिक राष्ट्र थे, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। इस शब्द को 2001 में जिम ओ 'नील ने रखा था।
- उस समय, ओ नील, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे। 2010 में चार देशों के शामिल होने के पीछे मूल विचार, जो कि 2010 में पाँच हो गए, एक समूह में यह था कि ये सभी देश प्रमुख विकासशील देश हैं जिनमें मजबूत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
- ये राष्ट्र जी -20 का हिस्सा हैं, जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और सरकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यह समिति क्षेत्रीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- यह अनुमान लगाया जाता है कि ब्रिक्स के पाँच सदस्य देशों में विश्व की कुल आबादी का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा शामिल, लेकिन पुराना मित्र हमेशा काम आता है, यदि आज भारत और रूस के संबंधों में पहले वाली गर्माहट बनी रहती तो ब्रिक्स में भारत को उतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी आशा की जानी चाहिये कि इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिये बेहतर रहेगा।
- भारत के लिये एक अन्य प्रमुख चिंता है- चीन की 'ब्रिक्स-प्लस' योजना। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स-प्लस, ब्रिक्स के विस्तारीकरण का एक सुझाव है और चीन चाहता है कि इस विस्तारित संस्करण में पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको को शामिल किया जाए। भारत ने पाकिस्तान को इस समूह में शामिल किये जाने का विरोध किया है।
- भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर रूस अब चीन के ज्यादा करीब है और ब्रिक्स-प्लस की अवधारणा का सूत्रपात करने वाला भी वही है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी नई अफगान नीति जारी की है, जिसमें भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की बात की जा रही है। इससे ब्रिक्स देशों की अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर अलग-अलग राय बन सकती है, जबकि अब तक इन मुद्दों पर ब्रिक्स सदस्य एक ही विचार रखते आ रहे हैं।
- ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जो विकासशील हैं और जिनके उद्देश्य विकसित देशों से भिन्न हैं। यदि ब्रिक्स मजबूत होता है तो विकासशील देशों की आवाज मजबूत होगी।
- भारत का न केवल चीन के साथ रणनीतिक मतभेद है, बल्कि रूस के साथ भी रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। हाल ही में रूस ने अपने एमआई-35 एम हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचे हैं, जिस पर भारत ने आपत्ति जाहिर की थी।
- साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं, परन्तु रूस का चीन-पाकिस्तान खेमे में जाना चिंतित करने वाला है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का जैसा व्यक्तित्व है, भारत को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। विदित हो कि अपनी नई अफगान नीति के संबंध में वक्तव्य देते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत को अफगानिस्तान की मदद इसलिये करनी चाहिये क्योंकि उसने अमेरिका से लाखों डॉलर कमाए हैं।
- कुल मिलाकर कहें तो आज वैश्विक परिस्थितियाँ पहले से ज्यादा परिवर्तनशील हैं और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए भारत ने गुटनिरपेक्ष को अधिक महत्त्व देना बंद कर दिया है। लेकिन पुराना मित्र हमेशा काम आता है, यदि आज भारत और रूस के संबंधों में पहले वाली गर्माहट बनी रहती तो ब्रिक्स में भारत को उतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी आशा की जानी चाहिये कि इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिये बेहतर रहेगा।
- भारत के लिये एक अन्य प्रमुख चिंता है चीन की 'ब्रिक्स-प्लस' योजना। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स-प्लस, ब्रिक्स के विस्तारीकरण का एक सुझाव है और चीन चाहता है कि इस विस्तारित संस्करण में पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको को शामिल किया जाए। भारत ने पाकिस्तान को इस समूह में शामिल किये जाने का विरोध किया है।
- भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर रूस अब चीन के ज्यादा करीब है और ब्रिक्स-प्लस की अवधारणा का सूत्रपात करने वाला भी वही है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी नई अफगान नीति जारी की है, जिसमें भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की बात की जा रही है। इससे ब्रिक्स देशों की अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर अलग-अलग राय बन सकती है, जबकि अब तक इन मुद्दों पर ब्रिक्स सदस्य एक ही विचार रखते आ रहे हैं।

संभावित प्रश्न

हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिक्स सम्मेलन, 2017 में सभी की नजरें भारत-चीन के मध्य बनते-बिगड़ते संबंधो पर टिकी हुई थी। इस कथन के सन्दर्भ में वर्तमान में भारत-चीन संबंधो में व्याप्त गतिरोध के कारणों की चर्चा कीजिये, साथ ही बताये कि इस सम्मेलन के परिणामस्वरुप दोनों देशों के संबंधो पर क्या प्रभाव पड़ेंगे?